भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3924
(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सी-पीएसीई के माध्यम से हटाई गई कंपनियाँ

3924. श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर में कार्यरत एमएसएमई, एलएलपी और निजी कंपनियों के बीच त्वरित कारपोरेट निकासी प्रसंस्करण केंद्र (सी-पीएसीई) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) क्या उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से स्वैच्छिक निकासी या कंपनियों के हड़ताल के लिए कोई आवेदन सी-पीएसीई के माध्यम से संसाधित किए गए हैं; और
(ग) यदि हाँ, तो ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है और पूरा होने में औसतन कितना समय लगा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): मंत्रालय ने अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाली कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की है जो 01.05.2023 से चालू है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र वाले एलएलपी के स्वैच्छिक समापन को सुविधाजनक बनाने और तीव्र करने के लिए 27.08.2024 से सी-पीएसीई के तहत भी लाया गया है। देवास-शाजापुर जिले आरओसी, ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आते हैं और आवेदनों की संख्या और स्ट्राइक ऑफ में लगने वाला औसत समय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**जिला**	**बंद कंपनियों की संख्या**	**पूरा होने में लगने वाला औसत समय**
01-05-2023 से 31.03.2024	देवास	02	75.40 दिन
	शाजापुर	03	
04-04-2024 से 31-03-2025	देवास	02	60.67 दिन
	शाजापुर	01	
01-04-2025 से 31-07.2025	देवास	03	51 दिन
	शाजापुर	02	
कुल		**13**	**62.3 दिन**

****